अब आपने सुझाव दिया है, तो हम संबंधित पक्ष के जितने भी लोग हैं, हमारे जितने माननीय सांसद इसमें अपनी राय देना चाहते हैं, उनको बुलाएंगे और बैठकर बात करेंगे।

श्री सभापति: उन्होंने संबंधित मंत्रियों, मंत्रालय और राज्यों के बारे में पूछा है।

SHRI MAJEED MEMON: A country-wide general strike by major national trade unions would paralyse the entire system and cause great hardships to the people in general. Has the hon. Labour Minister examined the legitimacy of the unions' demand and is the Government taking all possible efforts to avert this strike?

श्री संतोष कुमार गंगवार: मैं आपकी बात से सहमत हूँ और जैसा मैंने बताया कि हमने पिछले तीन वर्षों में 98 प्रतिशत मांगों का समाधान कराया है। इसके बाद भी आप जो सुझाव दे रहे हैं, उनके हिसाब से हम सभी संबंधित पक्षों को बुलाकर बात करेंगे।

SHRI BINOY VISWAM: Accepting the fact that the workers are the real creators of wealth, would the Government be prepared for a change in their stance which is anti-worker today?

श्री संतोष कुमार गंगवार: मैं आपकी बात पर अभी कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन इतना अवश्य है कि श्रम कानून, जो अब तक 44 थे, उनको हम एक सुविधाजनक तरीके से चार लेबर कोड्स में बदलने का काम कर रहे हैं। आप जो सुझाव दे रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इस संदर्भ में भी श्रम संगठन या कोई और सांसद कोई सुझाव देंगे, तो हम उसे entertain करेंगे।

Steel industry under debt burden

*94. SHRI MANISH GUPTA: Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) whether the steel industry in the country is heavily debt burdened, if so, the details thereof;

(b) whether rising raw material costs, power costs and global competition is slowing production and demand, if so, the measures being initiated by Government to obviate these difficulties;

(c) whether the targets for achieving a higher steel production capacity of around 300 million tonnes by 2030-31 is making progress, as the present capacity is less than 100 million tonnes; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STEEL (SHRI DHARMENDRA PRADHAN): (a) to (d) A Statement is laid on the table of the Home.

Statement

(a) No, Sir. Steel is a capital-intensive industry with long gestation period. Steel companies require capital for activities such as capacity expansion and technological upgradation. The ideal Debt to Equity ratio for capital intensive and long gestation period sectors like power and steel is 2:1. The Indian steel sector Debt to Equity ratio is presently less than 2:1.

(b) No, Sir.

(c) and (d) Yes, Sir. The capacity for domestic crude steel production expanded from 109.85 MT in 2014-15 to 142.24 MT in 2018-19. Already, capacity addition to the tune of about 28 MTPA is underway.

SHRI MANISH GUPTA: Sir, the problem afflicting the major steel units, has also now started afflicting the mid-size firms. Inventory is high, debtor days have been extended and most mid-level steel companies are now contemplating job cuts. The credit crunch and slowdown in auto and real estate sector has also affected this industry since it depends on the broader economy.

श्री धर्मेंद्र प्रधान: सर, मैं आपके माध्यम से आदरणीय सदस्य को यह सूचित करना चाहूँगा कि अभी अक्टूबर महीने के तथ्य सामने आए हैं। हाँ, यह सत्य है कि स्टील इंडस्ट्री, विशेषकर विश्व में जो स्थिति बनी, अमेरिका और चाइना के बीच जो एक व्यावसायिक विवाद बना, उससे सबसे अधिक hostage में कोई आया, तो स्टील इंडस्ट्री आई। यह दुनिया भर में हुआ। विश्व में हमारे कई देशों के साथ एफटीए एग्रीमेंट हैं। कुछ मित्र देशों को हमारे बाजार को accessibility देनी पड़ती है। भारत में इन दिनों डिमांड की जो स्थिति बनी, अगस्त-सितम्बर में भी ऐसी स्थिति थी, लेकिन अक्टूबर आते-आते बाजार की मिड साइज़ स्टील मिल्स की हालत धीरे-धीरे सुधरी है, थोड़ी डिमांड भी सामने आई है। इन दिनों एक और महत्वपूर्ण निर्णय भारत सरकार ने किया है कि प्रधान मंत्री जी ने आरसीईपी में नहीं जाने का निर्णय किया है। अगर उससे सीधा-सीधा कोई लाभार्थी होता है, किसी पर सकारात्मक impact होता है, तो स्टील इंडस्ट्री पर होता है। इन दिनों मैं सदस्य की आशंका को स्वीकार करता हूँ, लेकिन स्थिति ऐसी नहीं है, धीरे-धीरे इसमें progress हो रही है।

SHRI MANISH GUPTA: Sir, research and development in the steel sector has to be done by utilising tripartite synergy amongst industry, both private and public, national R&D laboratories and academic institutions. How has the Steel Research and Technology Mission of India been able to spearhead these efforts?

श्री धर्मेंद्र प्रधान: सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज भारत high-end steel का नेट इम्पोर्टर है। हमें अपनी आवश्यकता के लिए जो 5-7 मिलियन मीट्रिक टन का नेट इम्पोर्ट करना पड़ता है, उसमें strategic sector के लिए तथा विशेष आवश्यकता के लिए इम्पोर्ट करना पड़ता है। भारत धीरे-धीरे अपनी ही R&D पर जोर देते हुए world class technology adoption तथा internal research and development के माध्यम से उस दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। सर, मैं आपके संज्ञान में यह बात भी रखूँगा कि मिधानी और नाल्को भले ही एल्युमीनियम से संबंधित हों, लेकिन आज हमारे देश में मिधानी एक बड़े संयंत्र के रूप में emerge कर रहा है। हमारी strategic sector की high-end steel से संबंधित R&D में जो रिसर्च सामने निकलकर आती है, उसमें भी हमने काफी आगे तक प्रगति की है।

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, the Minister has repeatedly said that steel is a strategic sector. My question to him is, in recent weeks, the Government has decided to privatise strategic sectors. Is there a plan or is he just thinking that SAIL also, which is strategic, is going to be privatised like BPCL and other companies?

श्री धर्मेंद्र प्रधान: सभापति महोदय, जयराम जी की एक पुरानी आदत है, कहीं से कहीं चले जाना। मैं बहुत आदर के साथ उनको बताना चाहता हूँ कि वे बड़े अनुभवी सदस्य हैं, लेकिन मेरा उनसे निवेदन है कि वे संसद को गुमराह न करें, चतुराई का दुरुपयोग न करें। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मैंने कहा कि देश में strategic sector की स्टील की requirement 7-8 मिलियन मीट्रिक टन है। मैंने केवल यही कहा। आप ही के कृत्य के कारण आज हमको इम्पोर्ट करना पड़ रहा है। आज हम अपने ही पैर पर खड़े होकर उसमें धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आपने भी कुछ अच्छे काम किए हैं। स्टील सेक्टर के लिए आपने भी काम किया था और हमने भी उसे आगे बढ़ाया। स्टील एक deregulated industry हो चुकी है। आज हमारे देश की कैपेसिटी 140 मिलियन मीट्रिक टन बन चुकी है। ...**(व्यवधान)**... मैं वहाँ तक आ रहा हूँ देखिए, need based strategic disinvestment हमारी नीति है। The Government has no business to be in business, यह हमारा दृढ़ मत है और इस विचार से ही हम लोगों का mandate लेकर आए हैं। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Shri N. Gokulakrishnan. ...*(Interruptions)*... He said that the Government has no business to be in business. Shri N. Gokulakrishnan. ...*(Interruptions)*... That is his statement. You can discuss it.

श्री आनन्द शर्मा: सर, इस पर चर्चा होनी चाहिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: आनन्द शर्मा जी, प्लीज़। मैंने गोकुलकृष्णन जी को बुलाया है।

SHRI N. GOKULAKRISHNAN: Sir, the Government is not coming forward to safeguard the domestic steel industries. The bank has to facilitate domestic steel industries to bring back production. Would the Government be prepared to help the domestic steel industries or not?

श्री धर्मेंद्र प्रधान: सर, सरकारी बैंकों ने अक्टूबर महीने में ढाई लाख करोड़ रुपया public lending किया है। हम सारे लोग पब्लिक डोमेन में हैं। अगर उसका कोई एक बड़ा वर्ग लाभार्थी है, तो वह एम.एस.एम.ई. है। उसके साथ-साथ, mid-sized steel mills भी उसके बड़े लाभार्थी हैं।

Lack of basic facilities in slums

*95. SHRI RAJMANI PATEL: Will the Minister of HOUSING AND URBAN AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether a large percentage of slum population in the country still lives without any basic facilities/amenities including access to clean drinking water and sewage disposal as per the latest census;

(b) if so, the details thereof indicating slum population and number of households living in slums without basic facilities and the number of Scheduled Castes/Scheduled Tribes therein, State/UT-wise;

(c) the details of schemes/programmes run by Government to provide basic facilities/amenities to slum dwellers; and

(d) the details of funds allocated for the purpose and targets fixed and achieved during each of the last three years?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS (SHRI HARDEEP SINGH PURI): (a) to (d) A Statement is laid on the table of the Home.

Statement

(a) and (b) As per Census of India-2011, out of 4,041 statutory towns, there are 2,613 slum reported towns. Total slum population residing in these towns was 6,54,94,604; out of which 2,25,35,133 lived in notified slums. Out of total slum population of 6,54,94,604, population belonging to Scheduled Castes was 1,33,54,080 (20.4%) and population belonging to Scheduled Tribes was 22,16,533 (3.4%). State-wise details of slum population are given in the Annexure-I (*See* below).